

न्यूज़ दुड़े

उच्चतम न्यायालय ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स (telcos) को समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue:AGR) बकाये के भुगतान हेतु 10 वर्ष की समयावधि प्रदान की है।

- निर्णय के तहत दूरसंचार कंपनियों को अपने कुल AGR बकाया राशि का 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान, 31 मार्च 2021 तक करना होगा तथा शेष राशि की चुकौती उन्हें आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में करनी होगी।
- SC ने दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications: DoT) द्वारा भुगतान के लिए की गई 20 वर्षीय मांग को खारिज कर दिया है और बकाया राशि के पुनर्मूल्यांकन को भी अस्वीकार कर दिया है।
- AGR सरकार और दूरसंचार कंपनियों के मध्य एक शुल्क-साझाकरण तंत्र है, जिसे वर्ष 1999 में निर्धारित लाइसेंस शुल्क मॉडल (fixed license fee model) से राजस्व-साझाकरण शुल्क मॉडल (revenue-sharing fee model) में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- इस मॉडल के तहत, दूरसंचार कंपनियों द्वारा केंद्र सरकार को राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए प्रयुक्त की जाने वाली राजस्व राशि को ही AGR के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- **AGR संबंधी विवाद**
 - DoT के अनुसार, राजस्व गणना में एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा अर्जित सभी प्रकार के राजस्व शामिल होने चाहिए, जिसमें गैर-दूरसंचार खोतों जैसे व्याज जमा और परिसंपत्तियों की बिक्री आदि से प्राप्त राजस्व भी समाहित होना चाहिए।
 - दूरसंचार कंपनियों का मत है कि AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को ही शामिल किया जाना चाहिए और गैर-दूरसंचार राजस्व को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।
 - अक्टूबर 2019 में, उच्चतम न्यायालय ने AGR के हिस्से के रूप में समाप्ति शुल्क (termination fee) और रोमिंग शुल्क (roaming charges) को छोड़कर सभी राजस्व को शामिल करने का आदेश दिया था।

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana: PMKSY) के तहत 27 शीत-श्रृंखला परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है

- इन परियोजनाओं को PMKSY की एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना (Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure) योजना के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया है। इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक, नवीन अवसंरचनात्मक और प्रभावी शीत श्रृंखला सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी।
 - PMKSY का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों (retail outlet) तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से युक्त एक आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है।
- देश में शीत श्रृंखला अवसंरचना अपर्याप्त होने के साथ-साथ इसके वितरण की स्थिति भी निम्नस्तरीय बनी हुई है, जिसके कारण देश में खाद्य पदार्थों की अत्यधिक बर्बादी होती है। उदाहरण के लिए: शीत-श्रृंखला के अभाव के कारण 4.6-15.9% फल और सब्जियों तथा लगभग 2.7% मौस सादि का वर्ष्य व्यय हो जाता है।
- परियोजनाओं के लाभ: इनसे कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने, किसानों एवं अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेहतर मूल्य प्रदान करने तथा संबद्ध क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने में सहायता प्राप्त होगी।
- शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन तथा परिस्करण अवसंरचना योजना (Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure Scheme) के बारे में
 - इसका उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी अवरोध के एकीकृत शीत श्रृंखला और परिस्करण अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है।
 - इसमें संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है, जैसे: पूर्व-शीतलन, भार मापन, पृथक्करण, श्रैफीकरण आदि।
 - इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

भारत और 3 अन्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की मांग की गई है

- भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने UNSC में सुधार प्रक्रियाओं में तेजी लाने का आह्वान किया है। साथ ही, इन राष्ट्रों द्वारा यह मुद्दा भी उठाया गया था कि इस मुद्दे पर अंतर्र-सरकारी समझौता वार्ताओं (Intergovernmental Negotiations:IGN) से एक दशक से भी अधिक समय से कोई अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।
 - इन चार देशों को G4 के रूप में जाना जाता है, जो एक विस्तारित UNSC में स्थायी सीटों पर निर्वाचन के लिए एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं।
 - IGN, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत वर्ष 2009 में गठित एक समूह है, जो UNSC सुधारों पर विचार कर रहा है।
- G4 ने UNSC को कॉमन अफ्रीकन पोजिशन (Common African Position: CAP) के अनुरूप रूपांतरित करने की कार्रवाई की भी मांग की है और स्पष्ट किया है कि वार्ता को उन देशों द्वारा बाधित किया जा रहा है, जो सुधारों के प्रति इच्छुक नहीं हैं।
 - UNSC के विस्तार के लिए CAP को अफ्रीकी संघ की एजुलविनी सहमति (Ezulwini Consensus) और सिर्ट घोषणापत्र (Sirte Declaration) के तहत निर्धारित किया गया है। दोनों ही दस्तावेज़ कम से कम 2 स्थायी और 2 से 5 अस्थायी UNSC सीटों को अफ्रीकी देशों को प्रदान किए जाने की मांग करते हैं।
- UNSC सुधार एंडें भी में 5 क्षेत्र शामिल हैं यथा:
 - सदस्यता की श्रेणियाँ;
 - पांच स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयुक्त वीटो से संबंधित प्रश्न;
 - क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व;
 - एक विस्तारित परिषद का आकार और उसकी कार्यप्रणाली तथा
 - सुरक्षा परिषद एवं महासभा के मध्य संबंध।

WHO PAYS HOW MUCH

The Supreme Court has given telcos 10 years—against the 20-year window that the DOT sought to pay a combined 1.4 trillion in dues.

TOTAL DUES (AS PER DOT ESTIMATES) (All amounts in crore)	Paid to DoT	Annual instalment
58,254 Vodafone Idea	7,854	5,040 (Without interest, for 10 years)
16,798 Tata Tele- services	13004 + 5000 (ad hoc)	2,598
43,980 Bharti Airtel	4,197	1,260
70.53 Reliance Jio	195.18 (as per Self- assessment)	NA

Annual instalment will attract an interest of 8%
Source: Supreme Court order

WHAT THE COURT SAID

20 YEARS for payment of AGR dues, as sought by DoT, is 'excessive' ; TELCOS must get reasonable time, considering the stress in the sector ; THERE is no room for dispute and for reassessment of the dues

भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर पहल (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI) का शुभारंभ किया गया

○ SCRI को भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार हेतु एक त्रिपालीय दृष्टिकोण के रूप में जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना और साझेदार देशों के साथ पारस्परिक रूप से पूरक संबंध स्थापित करना है।

➢ वर्ष 2019 में, इन 3 देशों का संचयी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 9.3 ट्रिलियन डॉलर तथा उनकी पूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार क्रमशः 2.7 ट्रिलियन डॉलर एवं 0.9 ट्रिलियन डॉलर था।

○ आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर यह पहल वस्तुतः एक राष्ट्र द्वारा एक या कुछ पर निर्भर होने की बजाय आपूर्ति करने वाले राष्ट्रों के एक समूह की सहायता से अपने आपूर्ति जोखिम को कम करने पर बल देती है।

➢ यह प्रतिकूल घटनाओं के बेहतर प्रबंधन और मूल्य अस्थिरता को अनुशासित करने में भी सहायता करेगी।

SCRi का महत्व

➢ चीन पर निर्भरता कम होगी।

➢ भागीदार देशों के मध्य सहयोग में वृद्धि होगी। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत पहले से ही अमेरिका के साथ चतुर्कोषीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) के भागीदार देश के रूप में संलग्न हैं।

➢ भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनः प्रारंभ करना सुविधाजनक होगा।

❖ SCRI, सुदूर आपूर्ति और विनिर्माण श्रृंखलाओं के निर्माण हेतु आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस) के साथ मिलकर कार्य कर सकती है, जो बाद आधात एवं प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना सकत है।

○ SCRI से भारत को प्राप्त होने वाले लाभ: यह भारत को 'मेक फॉर वर्ल्ड' (विद्युत के लिए विनिर्माण) के अनुरूप आपूर्ति हब के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करेगी, जापान के साथ व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगी आदि।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market: GTAM) का शुभारंभ किया गया

- GTAM, नवीकरणीय ऊर्जा के अल्पकालिक व्यापार हेतु एक विशेष मंच प्रदान करेगा तथा यह पहला मंच होगा, जहां नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable energy: RE) का प्रथम बार भौतिक व्यापार किया जाएगा।
- **GTAM की मुख्य विशेषताएँ:**
 - > GTAM अनुबंध के माध्यम से अनुसूचित ऊर्जा को, क्रेता का नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligations: RPO) अनुपालन माना जाएगा।
 - ❖ इससे पूर्व, पवन या सौर ऊर्जा कंपनी से विद्युत खरीदने वाले क्रेता यह दावा नहीं कर सकते थे, कि उन्होंने RPO अनुपालन को पूर्ण कर लिया है।
 - ❖ RPO तंत्र वस्तुतः एक दायित्व है, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा और स्टोरों से कुछ प्रतिशत विद्युत का क्रय करना पड़ता है।
 - > GTAM अनुबंधों को सौर RPO और गैर-सौर RPO में विभाजित किया जाएगा, क्योंकि इनके लिए RPO लक्ष्य भी भिन्न-भिन्न निर्धारित किए गए हैं।
 - > इसमें ग्रीन इंट्राडे (Green Intraday), डे अहेड कंटिंगेंसी (Day Ahead Contingency) तथा दैनिक और साप्ताहिक अनुबंध (Daily and Weekly Contracts) शामिल होंगे।
 - > मूल्य का निर्धारण निरंतरता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात् मूल्य अधिमान्य समय पर निर्धारित होंगे।

○ GTAM के लाभ

- > यह RE-समृद्ध राज्यों पर बोझ को कम करने के साथ-साथ अपने RPO के माध्यम से स्वयं की RE क्षमता को विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगा।
- > यह RE कारोबारी क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देगा और देश की RE क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
- > यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से RE के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। साथ ही, इसके तहत संपूर्ण देश के बाज़ार तक पहुंच प्राप्त होने से विक्रेताओं को भी लाभ प्राप्त होगा।

अन्य सुर्खियाँ

CITIIS (सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड स्टेन) कार्यक्रम (CITIIS (City Investments to Innovate, Integrate and Sustain) program)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को एकीकृत, नवाचार संचालित और संघारणीय शहरी अवसरंचना परियोजनाओं को लागू करने में सहायता प्रदान करना है। <ul style="list-style-type: none"> > यह कार्यक्रम अनुदान रूपी वित्तीय सहायता के माध्यम से चयनित शहरों को ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। ○ इस परियोजना को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के अधीन कार्यरत, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा समान्वित और प्रबंधित किया जा रहा है। ○ CITIIS, आवासन एवं शहरी कार्य मन्त्रालय (MoUHA), फ्रांसीसी विकास एजेंसी (French Development Agency: AFD) और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा समर्थित है।
फॉरेंसिक लेखांकन और जांच मानक (Forensic accounting and investigation standards (FAIS))	<ul style="list-style-type: none"> ○ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने FAIS पर विचार-विमर्श के लिए एक समिति का गठन किया है। ○ FAIS का उद्देश्य फॉरेंसिक और जांच में सर्वोत्तम प्रथाओं को संहिताबद्ध करना तथा इन क्षेत्रों में कार्य संचालन के लिए आधारस्थूल गुणवत्तायुक्त मानदंड निर्धारित करना है। ○ इससे भारत फॉरेंसिक लेखा और जांच मानकों का एक समुच्चय जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश बन जाएगा। ○ ICAI देश में चार्टर्ड अकाउंटेंटी के पेशे को विनियमित करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (Chartered Accountants Act, 1949) के तहत स्थापित एक साविधिक निकाय है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड बूरो की आत्महत्या और दुर्घटनावश हुई मृत्युओं पर वार्षिक रिपोर्ट (NCRB (National Crime Records Bureau) releases annual report on suicides and accidental deaths)	<ul style="list-style-type: none"> ○ मुख्य निष्कर्ष <ul style="list-style-type: none"> ○ आत्महत्या और दुर्घटनावश हुई मृत्युओं के मामलों में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में वृद्धि दर्ज की गई है। ○ शहरों में आत्महत्या की दर (13.9%) अखिल भारतीय औसत (10.4%) की तुलना में अधिक है। <ul style="list-style-type: none"> > आत्महत्या के प्रमुख कारण— पारिवारिक समस्याएँ, विवाह संबंधी समस्याएँ और चिरकालिक रोग हैं। > कृषि क्षेत्र में आत्महत्या की दर कुल आत्महत्याओं का 7.4% है। दैनिक वेतनभेदगियों के मध्य आत्महत्या की घटनाएं सर्वाधिक रही हैं। ○ दुर्घटना में मृत्यु के प्रमुख कारण यातायात दुर्घटनाएँ (43.9%), आकस्मिक मृत्यु (11.5%) और नदी, ताल आदि में डूबना (7.9%) रहे हैं।
पोषण माह (POSHAN Maah)	<ul style="list-style-type: none"> ○ प्रति वर्ष सिवंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ○ इस माह के दौरान पोषण जागरूकता और पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) से संबंधित गतिविधियों को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा ज़मीनी स्तर तक संपन्न किया जाएगा। ○ पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2018 में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया था।
रोबोट रक्षक (Robot Rakshak)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह रेलवे द्वारा डिज़ाइन किया गया एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट है, जो दूर से ही विकित्सक और रोगी के मध्य संवाद स्थापित कर सकता है। ○ यह तापमान, नाड़ी संपदन और ऑक्सीजन प्रतिशत जैसे स्वास्थ्य मापदंडों का मापन करने में सक्षम है। ○ यह रोगियों को दवाइयों व भोजन प्रदान करने के साथ-साथ विकित्सक और रोगी के मध्य दो-तरफा वीडियो संचार को भी स्थापित करने में सक्षम है।
परमाणु अपशिष्ट से निर्मित बैटरी (Battery made from nuclear waste)	<ul style="list-style-type: none"> ○ कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने कृत्रिम हीरे के खोल में कार्बन-14 (C14) परमाणु अपशिष्ट को संगृहीत कर सेल्फ-चार्जिंग बैटरी का निर्माण किया है। <ul style="list-style-type: none"> > कार्बन-14 (C14), या रेडियोकार्बन, कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इससे जीवित जीवाश्मों से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ आयु अनुमान उपलब्ध करवाने में सहायता प्राप्त होती है। यह पुरातत्व वस्तुओं के काल निर्धारण में सहायक है। ○ यह बैटरी रेडियोधर्मी अपक्षय के परिणामस्वरूप, हीरे के खोल में फैल गए और निष्केपित हो गए इलेक्ट्रोनों की बौछार से स्वयं विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम है। <ul style="list-style-type: none"> > कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 28,000 वर्ष तक कार्य कर सकती है।
कैलाश-मानसरोवर (Kailash-Mansarovar)	<ul style="list-style-type: none"> ○ हालिया भारत-चीन तनाव के मध्य चीन ने मानसरोवर झील के निकट सतह से हवा में मार करने वाले भिसाइल बेस का निर्माण किया है। ज्ञातव्य है कि यह झील कैलाश-मानसरोवर का एक भाग है। ○ मारंट कैलाश और मानसरोवर झील, जिसे सामान्यतया कैलाश-मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, चार धर्मों यथा- हिंदुओं, तिब्बती बौद्ध, जैन, बोन (तिब्बत के पूर्व-बौद्ध धर्म के अनुयायी) द्वारा पूजारीय है। ○ इस स्थल से चार नदियां प्रवाहित होती हैं यथा: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णली (गंगा की सहायक नदी)।
हम्पी (Hampi)	<ul style="list-style-type: none"> ○ हम्पी कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल (UNESCO World Heritage Site) है। ○ इसका नामकरण पम्पा (तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम) नदी के नाम पर किया गया था, जिसके तट पर यह शहर स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। ○ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इसे 1565 ईस्वी में (तालिकोटा के युद्ध में) दक्कन के मुस्लिम शासकों ने नष्ट कर दिया था। ○ प्रमुख स्थल: अच्युतराय मंदिर, विठ्ठल मंदिर, पट्टमिराम मंदिर, कमल महल आदि।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

